कमल संदेश

हमारा संकल्प 'विकसित भारत'

वर्ष-19, अंक-06  16-31 मार्च, 2024 (पावसक)  ₹20
भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 17 फरवरी, 2024 को भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश महावीर, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं श्री अमित शाह

वाराणसी में 23 सितंबर, 2023 को भारत की अमृत-पीढी के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विशेषांक

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 21 फरवरी, 2024 को सहकारी क्षेत्र के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का उदघाटन एवं सिलान्स करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल एवं श्री अजुनन मुंडा संसद भवन (नई दिल्ली) में 21 सितंबर, 2023 को महिला संसद सदस्यों के साथ ‘नारी सशक्त बदलना अधिनियम’ के पारंपरिक होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पोखरण (राजस्थान) में 12 मार्च, 2024 को टूट-सानिस फार्मिंग एवं युद्धलाय उद्योगक्रम 'भारत शक्ति' के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल मिश्रा, रक्षा मंत्री श्री असमत िक्स, श्री पीयूष गोयल एवं श्री अजुनन मुंडा

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 10 सितंबर, 2023 को जी20 प्रतिनिधिमंडल के साथ राजधानी का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
<table>
<thead>
<tr>
<th>विषय-सूची</th>
<th>पृष्ठमार्ग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. गरीबों को सेवा, वंचितों का सम्मान</td>
<td>06</td>
</tr>
<tr>
<td>2. किसानों का कल्याण सुनिश्चित</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3. नारी शक्ति – महिलाओं के नेतृत्व में विकास</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>4. भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>5. मध्यम वर्ग का जीवन आसान</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>6. सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>7. ‘राष्ट्र प्रथम’ विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>8. भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>9. व्यापार सुगमता</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>10. स्राफ़स्ट्रीकरण – प्रगति पथ</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>11. भारत का टेक्नोलॉजी युग</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>12. नॉर्थ-इंडिय : विकास का नया इंजन</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>13. विसात्ता और विकास</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>14. पर्यावरण और सतत विकास</td>
<td>62</td>
</tr>
</tbody>
</table>
बरेंद्र जोदी
बड़े लक्ष्यों को लेकर चल रहा आज का भारत प्रगति की तेज गति से समझौता नहीं कर सकता।

(11 मार्च, 2024)

अलिब शाह
मोदी जी के पास बीते 10 साल का ट्रैक ररकॉर्ड और आने वाले 25 साल का विज्ञान है।

(14 मार्च, 2024)

राजनाथ सिंह
हम लोगों ने CAA (Citizen Amendment Act), नागरिकता संशोधन कानून लागू करके आने वाले कानून को समाप्त करने वाला कानून नहीं है, बल्कि यह तो नागरिकता देने वाला कानून है।

(14 मार्च, 2024)

बी.एल. संतोष
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्री शंकराचार्य तह्स को श्वापूव्यक नमन करते हैं। चाहे वह जममू-कशमीर हो या पंजाब या तमिलनाडु या केरल या उत्तर पूर्व, ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र पूरे देश को एक साथ जोड़ रहा है।

(07 मार्च, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा
जब भारतीय जनता पार्टी ने अंतिमदेह का कार्यक्रम चलाया तब कोई इसका उपहार करती थी। हमने सदैव कहा है कि जब अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, तभी भारत का उदय होगा।

(7 मार्च, 2024)

रिज्जला तिरताकण
2005-06 के बाद से भारत में बहुआष्ठी गरीबों में उल्लेखनीय उदराम दज्य की गई है, जो 2013-14 के 29.17 प्रततशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रततशत हो गई है, इसमें 17.89 प्रततशत की कमी आई है। परिमार्जनस्वरूप विचलन 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआष्ठी गारीबों से बाहर आये हैं।

(15 जनवरी, 2024)
'अबकी बार, 400 पार'

से-जेसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ‘अबकी बार, 400 पार’ का नाम पूरे देश में गुजर चल रहा है। उन कर्तव्यों व प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो जन-जन के निरंतर बढ़ते विकास को प्रदर्शित कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का अपना विश्वास इसी बात से पता चलता है।

पीछे दस वर्षों की अविश्वसनीय उपलब्धियां, जिनसे आज सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं एजेंसियां चमकक्ष हैं, विकसित भारत के कंस्ट को सुदृढ़ कर रही है।

श्री नरेंद्र मोदी, जो पूरे देश के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे हैं, उन्होंने न केवल देश को इस दस्तकदार संक्षेप से निकाला, तबलीक अपने परिवर्तनकारी निष्ठाओं से उन ऊंचाइयों पर ले गए जहाँ से ‘विश्वसित भारत’ का स्वाभाविक अवसर साकार होता संभव दिख रहा है।

पीछे दस वर्षों में देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे जहाँ कहीं जनकांक्षा पूर्ण हुई हैं वहीं कहीं नई जनकांक्षा उपलब्ध्यां से प्रभावित। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को बड़ा सीधांत के लिए प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उन्होंने विश्वसनीय मंचों पर मानवता को सेवा का प्रति लिया दें ‘भारत की विश्वसित’ के रूप में नेतृत्व किया है। हर देश के साथ उनकी जुलूस के समय खुशी सहभाग से भरे देश नए तकनीक भर रहा है।

पीछे दस वर्षों की अविश्वसनीय उपलब्धियां, जिनसे आज सभी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं एजेंसियां चमकक्ष हैं, विकसित भारत के कंस्ट को सुदृढ़ कर रही है।
गरीबों की सेवा वंचितों का सम्मान

“डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हों, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है।”

– नरेन्द्र मोदी
गरीब कल्याण, देश का कल्याण

• गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
• 80 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
• जन धन योजना-वित्तीय समावेशन की विशेष में सबसे बड़ी पहल
• कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति और उनके अधिकारों की रक्षा
• डित्यांगजनों का सशक्तीकरण
• जनजातीय लोगों के लिए सर्वार्थ बिकास सुनिश्चित
• 3 करोड़ से अधिक प्रामाण्य गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध

दित्यांगजनों का सशक्तीकरण

• डित्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया
• सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आरक्षण क्रमशः 3% से बढ़ाकर 4% और 3% से बढ़ाकर 5% किया गया
• 25.94 लाख डित्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 14,175 शिविरों में सहायता और सहायक उपकरण बांटे गए
पीएम विश्वकर्मा - रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आसान ऋण

- कोविड‐19 महामारी के दौरान रेहड़ी‐पटरी वालों की गिरती मुक्त कर्ज की सुविधा दी गई।
- पीएम विश्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी‐पटरी वालों को मिला ऋण।

पीएम विश्वकर्मा योजना

- पीएम विश्वकर्मा 13 हज़ार करोड़ रुपये की लागत में केंद्र सरकार द्वारा विक्षेपित योजना।
- वायमेटिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से विश्वकर्माओं का निगमित पंजीकरण; पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पकलाएं शामिल।
- विश्वकर्मा भाई‐बहनों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण।
- 15 हज़ार रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन, कौशल उन्नयन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विषय उपयोग।

कमजोर वर्ग

आकांक्षाओं की पूर्ति?

- ईडब्ल्यूस के सलए नौकरों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण।
- राज्यों को खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार।
विशेषांक

दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल

• 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते
• लाभार्थियों के बैंक खातों में 32.29 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का डाउनसेफट बेनिफिट ट्रांसफर, 2.73 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित बचत (मार्च, 2022 तक)

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

• पिछले 9 वर्षों के दौरान 25 करोड़ भारतीय वित्तिय प्रकार की गरीबी से बाहर निकले
• गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गया
• भारत के 2030 से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना) हासिल करने की संभावना

80 करोड भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

• 1,424 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्य ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत वितरित किया गया (अप्रैल, 2020 – अक्टूबर, 2023)
• एक राज्य, एक राशनकार्ड से देश भर में लोगों को आसानी से मिल रहा राशन
• 2.5 करोड़ पोटेटोविलिटी लेनदेन का मासिक औसत
किसानों का कल्याण सुनिश्चित

“किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्रारंभिकता है।”

– नरेंद्र मोदी
पीएम किसान
• 2019 में शुरुआत, किसानों को 3 समान किस्टों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये
• पहली बार पूरे देश में शुरू किया गया प्रत्यक्ष नकद समान
• पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 11.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
• 2016 में शुरुआत, फसल शक्ति से पीड़ित किसानों की वित्तीय सहायता
• 49.5 करोड़ किसान आवेदकों का पंजीकरण, पिछले 7 वर्षों में 14.9 करोड़ से अधिक आवेदकों को 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का दायित्व हुए प्राप्त
• पंजीकृत किसानों में 84 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान

ई-नाम: जौजूदा बाजारों को ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया

मृदा स्वास्थ्य कार्ड
• मृदा में पोषक तत्वों के उपयोग में वृद्धि के लिए 2014-15 में योजना की शुरुआत
• किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किए गए जारी

अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष
मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोजन पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी और वैश्विक मांग का सुझाव करने के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2023 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित कर दिया।
सहकारी क्षेत्र में सुधार

- पिछले 25-30 वर्षों से सहकारी क्षेत्र में एक ठहराव देखने को मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

- श्री मोदी ने चीनी मिलों के लंबित 15,000 करोड़ रुपये के टेक्स्टिल विवाद का समाधान किया है।

- मोदी सरकार संवैधानिक दावे में सहकारी कानून में एकस्तरीय लागे के लिए काम कर रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

- एक विशेष अभियान के तहत सभी पीएम-किसान लाभार्थी केसीसी के माध्यम से कवर

- 8.85 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण-सुविधा के साथ 7.34 करोड़ से अधिक केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए (31 मार्च, 2023 तक)

पीएम-प्रणालि

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीई) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में ‘पीएम प्रोग्राम फॉर रेसटोरियन, अवेरनेस जनरेशन, नरिशेंट एंड ऐमेजरोशन ऑफ मदर अथ्व (पीएम-प्रणाम)’ को मंजूरी दी।

- इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के दिकार और संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने, वैमिनिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने के धर्ती के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए राष्ट्रों द्वारा शुरू किए गए जन अंदोलन का समर्थन करना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- उद्देश्य - ट्रांसफोम और स्विंगकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग में दक्षता बढ़ाना।
- 2015-16 से 78 लाख हेक्टेयर कवर
- नाबाद के तहत 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया।
- 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंतित।

कृषि अवसंरचना कोष

- कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा।
- योजना के कार्यान्वयन के 3 साल में 38,326 से अधिक परियोजनाओं का मंजूरी की गई है, जिसमें कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 30,030 करोड़ रुपये के कुल ऋण के साथ 38,326 से अधिक परियोजनाओं का मंजूरी है।
- 2015-16 से 78 लाख हेक्टेयर कवर
- नाबाद के तहत 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया।
- 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंतित।

कृषि अवसंरचना कोष

- कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा।
- योजना के कार्यान्वयन के 3 साल में 38,326 से अधिक परियोजनाओं का मंजूरी की गई है, जिसमें कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 30,030 करोड़ रुपये के कुल ऋण के साथ 38,326 से अधिक परियोजनाओं का मंजूरी है।
- कृषि इन्फ्रा परियोजनाओं ने 5.8 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जबकि सालाना 3.7 लाख मीट्रिक टन खाद्य और 46.3 लाख मीट्रिक टन वागवानी संबंधी उत्पादन की बचत की है और किसानों को 20-25% की सीमा तक बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की है।
नारी शक्ति
महिलाओं के नेतृत्व में विकास

“आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति-निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।”

- नरेन्द्र मोदी
नारी शक्ति वंदन अधिनियम

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था।

• इस अधिनियम से भारत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम।

• आरक्षित कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण।

• यह अधिनियम लैंगिक समानता और समावेशी समाज के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

• यह कानून महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
विशेषांक

उज्ज्वला योजना

तब

2014
14.52 करोड़
घरों में एलपीजी कनेक्शन

अब

2023
31.54 करोड़
घरों में एलपीजी कनेक्शन

वित्त वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए जायेंगे, जिससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ होगी

भारत में एल पी जी कवरेज
सख्त कानून

- तीन तलाक का अपराधीकरण
- मुस्लिम महिला की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित
- तीन तलाक के मामलों में उल्लेखनीय कमी
## महिलाओं का जीवन बना आसान

- 2019 में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास था नल कनेक्शन
- जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर, 2023 तक 10 करोड़ से अधिक नने परिवारों को मिला नल से जल

## महिला हेलपलाइन

- 1 अप्रैल, 2015 को महिला हेलपलाइन 181 शुरू की गई जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल के जरिए 24 घंटे आपत्तिकालीन और गैर-आपत्तिकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करती है

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

- पीएमएमवीवाई के तहत 3.11 करोड़ सल्यूशन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 14,103 करोड़ रुपये वितरित

## महिलाओं के जीवन में सुधार

### गरिमा
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.74 करोड़ शौचालय
- पीएमएवाई-जी के तहत बने 2.5 करोड़ से अधिक घरों में से 70% की अकेले या समय रूप से मालिक हैं महिलाएं
- तीन तलाक को गैर-कानूनी किया

### जीवन सुगमता
- 10 करोड़ से अधिक उज्वला एलपीजी कनेक्शनों से महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति
- मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह
- जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक नये परिवारों को मिला ‘नल से जल’

### उद्यमिता
- जनधन खातों के द्वारा 28 बैंकों से जुड़ीं
- स्टैंड अप इंडिया के तहत 79% उद्यमी महिलाएं हैं
- मुद्रा योजना के तहत 69% से अधिक खाता धारक महिला उद्यमी
भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त

“विकसित भारत के विज्ञ को लेकर देश की अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं।”

– नरेन्द्र मोदी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

• परिवर्तनकारी सुधार: 1986 की 34 साल पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव
  निष्ठा शिक्षकों की सामग्री शिक्षा विद्यालय मेलां में आधारित मार्गदर्शन
  विकास और पाठ्यक्रम विषयों के रचनात्मक संयोजन के साथ, एकाधिक प्रवेश/निकास के
  विकल्प
  क्रेडिट का एकेडसिक बैंक शैक्षणिक अंकों को
  टिजिटलि डिलिवर करना
  परमाणु भारत आधारभूत साक्षरता
  और संख्यात्मकता
  14,500 से अधिक पीएम श्री शैक्षणिक संस्थानों में से
  चयित 6,207 स्कूलों को पहली किस्त के
  रूप में कुल 6 दसौड़ रुपये जारी
  7 अगस्त, 2023, तक 12 संस्थानों को
  ‘उत्कृष्ट संस्थान’ (आईआई) के रूप में
  अधिसूचित किया गया

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आईटीआई)

• भारतीय संस्थान ने उद्योग 4.0 में
  जागरूकता और कौशल, रीसिकलिंग और
  अपरिस्थति कार्यवाल को बढ़ाने के लिए
  4 सर्वेक्षण उद्योग केंद्रों के माध्यम से क्षमता
  निर्माण की पहल शुरू की
  7 जुलाई, 2023 तक 7.26 लाख उम्मीदवारों
  को 288 जान शिक्षण संस्थानों (जेएसएस)
  के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया
  सांजीवाद (तीनान) और अबू धाबी
  (यूएई) में आईआईटी के नए परामर्शों की
  स्थापना से उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण
  की दिशा में एक प्रेरणात्मक शुरुआत

विशेषांक

टिकल इंडिया निधन

पीएम कौशल विकास योजना

युवाओं की
रिश्ता कौशल प्रशिक्षण
1.38 करोड़
युवा प्रशिक्षित
54.27 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को किया
गया अपस्किल और रीसिकल

11,847
2014

2023

14,955
शिक्षा का बुनियादी ढांचा

2014 - 2023

IIT: 16 - 23
IIIT: 9 - 25
IIM: 13 - 20
AIIMS: 8 - 23

2013-14 के बाद से कुल खर्च हुआ दोगुना

(शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त व्यय)
(लाख करोड़ रुपये में)
वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा

देश में अटल टिक्करिंग लैबों की संख्या 10,000 से अधिक ये 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 722 जिलों में फैले हुए हैं।

इसके लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), टार्टर्स इंडिया फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फाउंड्री टार्टर्स (CGSI) जैसी योजनाएं स्टार्टआप्स को समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टआप इंडिया फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फाउंड्री टार्टर्स (CGSI) जैसी योजनाएं स्टार्टआप्स को समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टआप इंडिया फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फाउंड्री टार्टर्स (CGSI) जैसी योजनाएं स्टार्टआप्स को समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS), स्टार्टआप इंडिया फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फाउंड्री टार्टर्स (CGSI) जैसी योजनाएं
खेल प्रतिस्पर्धाओं में चमकता भारत

हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 और एशियाई पैरा खेलों में 111 से अधिक पदक हासिल किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के मेजर ध्वनिचंद्र स्टेडियम में एशियाई खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारतीय एथलेटों से मुलाकात की।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के साथ भारत अनेकता में एकता को मना रहा है।

“एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत देने और संवाद बढाने का एक प्रयास है।”

– नरेन्द्र मोदी
मध्यम वर्ग का जीवन आसान

“हमारा लक्ष्य सभी का कल्याण और भलाई है। हमारा लक्ष्य सबका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है।”

– नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

• वर्ष 2016 में शुभारंभ
• ग्रामीण लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं
• 2.5 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा

विशेषांक

स्वच्छ भारत निशन-शहरी

• शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और शहर के ठोस कचरे का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य
• 20 करोड़ से अधिक नागरिक सीधे तौर पर जुड़े; 67.13 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.52 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
• 4,884 शहर व कस्बे ‘खुले में शौच से मुक्त’ घोषित

‘एक तारीख, एक घंटा, एक साथ’

देशभर में 8.75 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ‘एक तारीख, एक घंटा, एक साथ’ कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण पेश करते हुए, 1 अक्टूबर, 2023 को ‘स्वच्छता के लिए श्रमदान’ किया।
विशेषांक

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य ठोस और तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से गांवों की ओडीएफ़ स्थिति को बनाए रखना है।
• 4.61 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया।
• महिला सव्वं सहायता समूह स्वास्थ्य संस्थान पेटीफर कॉर्पोरेट प्रबंधन का कार्य संभाल रही हैं, जिससे आय सृजन के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

• जलपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने का लक्ष्य
• 1.72 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए; 1.35 करोड़ सीवरेज कनेक्शन दिए गए
• 3,340 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवरेज शोधन संयंत्र जोड़े गए
• 2,525 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और लगभग 4,603 एकड़ हरित क्षेत्र एवं पार्क विकसित किए गए
हर घर जल

• अगस्त 2019 में शुभारंभ, जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल जोड़ना उपलब्ध कराना।
• पानी समितियां; जन आंदोलन; समुदाय का स्वामित्व और महिलाओं की केंद्रीय भूमिका

रोजगार जेला

• 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान। अधिक से अधिक रोजगार सुलभ करने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है।
• सितंबर, 2017 से जुलाई, 2023 के बीच 5.5 करोड़ नए ईपीएफओ ग्रामीण घरों के साथ जोड़े गए।

सौभाग्य योजना

25 सितंबर, 2017 को घोषित
ग्रामीण और शहरी परिवारों को जल जीवन मिशन उपलब्ध कराने का उद्देश्य
अक्टूबर, 2017 तक: 89 प्रतिशत घर विद्युतीकृत
लॉन्च के बाद से 31/03/2022 तक 2.86 करोड़ परिवारों की विद्युतीकृत किया गया
2022: 100% ग्राम विद्युतीकृत

2019 से पहले 3.23 करोड़ परिवारों को नल से जल आपूर्ति की सुविधा थी
अक्टूबर, 2023 तक 13.52 करोड़ परिवारों के पास हैं नल से जल का कनेक्शन
सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा

“हमने तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न घड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिले।”

– नरेन्द्र मोदी
आयुष्मान भारत

पीएम-आयुष्मान भारत हेलथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन
• 25 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरक्षण के निर्माण एवं उन्नयन की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना
• वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि में 64,180 करोड़ रुपये की कुल लागत

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
• स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 27 सितंबर, 2021 को किया गया शुभारंभ
• 48 करोड़ से अधिक आभा (एबीएरए) नंबर और 2.39 लाख स्वास्थ्यकर्मी पंजीकृत
• 2.22 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी या निजी क्षेत्र के अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, फार्मासियों, क्लिनिकों आदि सहित) शामिल

‘आयुष्मान भव’ अभियान
• एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पहल जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्णता क्षेत्र प्रदान
करना है

ई-संजीवनी ओपीडी
• 1.05 करोड़ से अधिक ई-संजीवनी ओपीडी परामर्श दिए गए
अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार

• 15 नए एम्स और 319 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए।
• वर्ष 2014 से 2023 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1.08 लाख हुई। साथ ही स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 70,000 से अधिक हुई।

अंगदान से जीवनदान

• अंगदान को आसान बनाने के उद्देश्य से NOTTO की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए अंगदान का संकल्प दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।
• 2014 में सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर की अवधारणा पेश की, जो एम्बुलेंस के लिए खाली कराया गया सीमांस्कित विशेष सड़क मार्ग है। ये प्रतिरोध प्रणाली के लिए प्राप्त अंगों को गति अस्पताल तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
• 2013 में देश में पांच हजार से कम अंगदान हुए थे, लेकिन 2022 में यह संख्या 15 हजार से अधिक हुई।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

• देशभर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाएं पर अच्छी दवाइयाँ
• 2014 से 2023 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1.08 लाख हुई। साथ ही स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 70,000 से अधिक हुई।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान

• टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
• को-विन द्वारा अब तक 102.74 करोड़ से अधिक पहली डोज के प्रमाण पत्र, 95.21 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के प्रमाण पत्र और 22.87 करोड़ से अधिक प्रिकोज्वानरी डोज के प्रमाण पत्र जारी
• उपरांत इलाकों में कोविड-19 के टीकों की ड्रोन आधारित आपूर्ति

मादक पदार्थ के आदी लोगों का पुनर्उत्पाद

• नशा मुक्त भारत अभियान युवाओं को नशीली पदार्थों के प्रयोग के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू किया गया
• 10.6+ करोड़ लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में जागरूक किया गया
• देश भर में 638 सरकार समर्थित परामर्श केंद्र, उपचार और नशामुक्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन तक आसानी से पहुंच ले जियो-टॅग भी की गयी है
• नशा करने वालों को प्राथमिक परामर्श प्रदान करने के लिए ‘14446’ राष्ट्रीय नशामुक्ति टोल हेल्पलाइन शुरू की गईं

बाल स्वास्थ्य एवं प्रोत्साहन

मिशन इंद्रधनुष

• मिशन इंद्रधनुष (एमआई) का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाकर बच्चों का पूर्ण टीकाकरण तथा गर्भवती महिलाओं के बीच इस कवरेज को 90% करना और उसके बाद इसे निर्मलता रखना है।
• मई, 2022 तक 4.45 करोड़ बच्चों और 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण

‘14446’
राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान टोल हेल्पलाइन
‘राष्ट्र प्रथम’ विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा

हमें दुनिया के हर वर्ग, हर देश, हर समाज, हर रीजन को जोड़ना होगा। और यही एक परिवार की भावना है।” – नरेन्द्र मोदी
जी 20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली की सफलता

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनभागीदारी के दृष्टिकोण ने जी–20 कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गों की शामिल किया।
• 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकों ने जी–20 आयोजन के लिए एक अभूतपूर्व माहौल पैदा किया। परिणामस्वरूप, भारत की जी–20 अध्यक्षता वास्तव में जन–केंद्रित थी और एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में उभरी।
• नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने भारत की समकालीन प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ-साथ हमारी विरासत, संस्कृति और परंपराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। जी–20 सदस्य देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने इसकी व्यापक सराहना की।

हलका लड़ाकू हेलीकॉप्टर

स्वदेशी रूप से विकसित हलके लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) को ‘प्रचंड’ नाम दिया गया है, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

जनमूर्ती एवं कब्जाए में घुसपेट की कुल घटनाएं

<table>
<thead>
<tr>
<th>साल</th>
<th>घटनाएं</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2009 का 3574, 2021 का 1723 देश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं
उग्रवाद और नकसलवाद

- उग्रवाद जनित हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी (2014 में 824 की तुलना में 2022 में 201 घटनाएं)
- सिविलियन और सेक्टर फोर्स की मौतों में 96% की कमी (2014 में 232 की तुलना में 2022 में 09 मौतें)

ऑपरेशन अजय

- इजरायल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने शुरू किया ‘ऑपरेशन अजय’
- स्थिति पर नजर रखने और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित

ऑपरेशन गंगा

- 23,000 भारतीयों को यूक्रेन से सफलतापूर्वक वापस लाया गया
- 18 देशों के 147 नागरिकों को भी बाहर निकाला गया
- 90 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई

ऑपरेशन कावेरी

- युद्धार्थ सूडान से 3,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया
- एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं क्रायोजन सेंटर्स में निशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था

ऑपरेशन दोस्त

- भारतीय सेना के क्षेत्रीय अस्पताल ने भूकंप प्रभावित तुर्की के हरेय प्रांत में 3,600 से अधिक लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई
- इलाज के लिए आए मरीजों की लगभग 1,200 लैब जांरें की गईं
आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण

कानून संबंधी विषय
• 890 केंद्रीय कानून लागू; 205 राज्य कानून रद्द किए गए; 130 राज्य कानून संशोधित और लागू; 
• आरक्ण लाभ का विस्तार

विकास संबंधी विषय
• पीएमडीपी का तेज क्रियान्वयन, जम्मू-कश्मीर में 58,47 रुपये की लागत से 53 पीएमडीपी परियोजनाओं पर कार्य जारी। लद्दाख में 21,441 करोड़ रुपये की लागत की 9 परियोजनाओं पर कार्य जारी। जम्मू-कश्मीर में 32 परियोजनाओं व लद्दाख में तीन परियोजनाओं के कार्य पूर्णतः/आशिक रूप से पूरे।
• जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए संट्रल सेक्टर योजना के तहत 28,400 करोड़ रुपये के कार्य की शुरुआत। इससे रुपये निवेश, पूर्वरोज्जवल व्यापक समाधान, जीएएसटी से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

अगिनपथ योजना
• अगिनपथ सशस्त्र बलों के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है, जो भारतीय सेना को युवा शक्ति, उच्च तकनीक से लैस और अध्यावृत्त दृष्टिकोण के साथ दुनिया में सध्येक्ष पैदा बनाने की दिशाएँ में कार्य करने जा रही है।
• सरकार ने 15 जून, 2022 को अगिनपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अभिवर्ती के रूप में चार साल की अवधि के लिए देर सी बीपी सेनाओं के ‘अधिकारी के रैंक से नीचे’ कैड्र में भर्ती किया गया।
• 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र है।

आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक
• इंसर्जन्सी के विरुद्ध अभियान, म्यांमार- 9 जून, 2015
• सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके- 28-29 सितंबर, 2016
• बालाकोट हवाई हमला- 26 फरवरी 2019
ये दर्शक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा।

— नरेन्द्र मोदी
विशेषांक महामारी के बावजूद सबसे तेज वृद्धि

- भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
- 2024 में 7.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक बनाती है।
- निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि और खपत में उछाल के कारण आर्थिक गतिविधियों में सुधार।

आधार-डीबीटी लिंकेज- नागरिकों का सशक्तीकरण, शासन में सुधार

- 120 करोड़ उपभोक्ता
- धन का सुधार एवं तेज प्रवाह
- सीधे लाभाधिकारी तक पहुंचवाना
- दोहराव एवं धोखाधड़ी में कमी

जीएसटी: एक राष्ट्र, एक कर

- 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च: जीएसटी में 17 प्रमुख करों और 13 उपकरों को शामिल करते हुए पूरे भारत को एक बाजार में तबदील किया गया।

क्या आप जानते हैं?

अप्रैल, 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सर्वविधिक 1.87 लाख करोड़ रूपये रहा जो साल दर साल जीएसटी राजस्व संग्रह से 12% अधिक है।

डीबीटी: लीकेज को हटाया

- 4.2 करोड़ नकली एवं जाली राशन कार्ड (2013-2021) को हटाया
- 4.11 करोड़ जाली/फर्जी/निक्रिय एलपीजी कनेक्शन समाप्त किये
- ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाली/फर्जी/अपात्र लाभाधिकारियों को हटाया

2.73 लाख करोड़ रूपये की बचत
यूपीआई: देश का सबसे बड़ा एकल खुदरा भुगतान प्लेटफॉर्म

- यूपीआई से विश्व के 40% डिजिटल लेन-देन अब भारत में हो रहे हैं
- यूपीआई क्यू आर कोड में 4.6 गुना की वृद्धि रही
- वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ लेन-देन हुए जो 5 वर्षों में 91 गुना वृद्धि है
- वित्त वर्ष 2022-23 में 139.15 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन हुए जो 5 वर्षों में 126 गुना से अधिक वृद्धि है

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: सामाजिक-आर्थिक रूप से उपक्रमित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन
- 25.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत
- गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण
- जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए
स्टार्टअप इंडिया:
- भारत में अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न
- वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में
- 669 जिलों में स्टार्टअप को मान्यता दी गई
- अब तक 9.5 लाख से अधिक रोजगार का सुझान
- वित्त वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा 2.7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ सुनिवित

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल
सबको बैंकिंग, सबको सूरक्षा और सबको वित्त पोषण
- 15 अगस्त 2014 को शुरुआत
- 34.26 करोड़ रुपये कार्ड जारी
- औसत जमा राशि 4,066 रुपये
- कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा

गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस:
- समावेशन, उपयोगिता, पारदर्शिता, दक्षता और लागत में वृद्धि
- पोर्टल ने 4.91 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वार्षिक खरीद दर्ज की (जुलाई, 2023 तक)
- ऑर्डरों की संख्या 1 करोड़ के पार, जिसमें से 55 प्रतिशत ऑर्डर मूल्य सूक्ष्म और लघू उद्योग से (जुलाई, 2023 तक)
- जेम (GEM) पर 8 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघू उद्योग सेवा प्रदाता पंजीकृत
“एक समय था जब कहा जाता था - Why India. अब जो Reforms देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है- ‘Why not India’ ” – नरेन्द्र मोदी
देश में व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं। अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने और पारदर्शिता पर जोर देने के साथ ही विभिन्न कानूनों एवं विनियमों के सरलीकरण से उल्लेखनीय बदलाव आया है।

• कानूनों के बोझ से मुक्त: 41,000 से अधिक अनुपालन समाप्त कर दिए गए।
• कंपनी कानून और एलएलपी कानून से संबंधित प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण: 2017 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और कई प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत बना दिया गया और नागरिक नुक्सानों के रूप में माना गया।
• कंपनियों पर कर का बोझ घटा: घरेलू कंपनियों के लिए अधिभार सहित प्रत्यक्ष कर को 30 प्रतिशत से घटाकर अधिभार और उपकर सहित 25.17 प्रतिशत कर दिया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

एफडीआई (अरब डॉलर में)

पीएलआई योजना
• भारत की एक वैश्विक वित्तीय योजना के रूप में स्थापित करता।
• आपले 5 साल के दौरान 14 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिवेदनता
• 60 लाख होनगडा सुरक्षित करने का त्योहार

स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का उभराने
• 100 से अधिक सुलभित का उभराने

समय में बदलते
• लिविङ्गकीय संसाधनों/ प्रशासन-पत्र हासिल करने के लिए वात-मंडल दिनिजल स्टेटफोर्म
• लिविंगकी की नजदीक के लिए जोड़ा लिंग सिंगल विपण (एफडीआई)

प्रक्रियाओं में आसानी
• व्यापारी इनपुटों के लिए तरह एक बेस एफडीआई एडिशन और एजाइल-प्रो-एस
• 41,000 से अधिक अनुपालनों को मुक्त कर दिया गया।

नीतिगत मुदार
• विभिन्न इंडियन एक्सचेंज एक्सचेंज (बीआईएच) 2022
• एफडीआई प्लांट का बढ़ावा
• भारतीय राष्ट्रीय आधिकारिक अवलोकन एवं विविध हासिल की आवश्यकता (आईबीए) को लगाव करना।
• अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए जन विश्वास (प्राधिक विश्वास) अधिनियम लागू। अधिनियम ने 19 अनुमोदन/विविधानों से एक 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध की क्षमा के हटाने दी हो।

ओद्योगिक गतिविधि
• भारत में नए ओद्योगिक नौकरियों का विकास
• 11 ओद्योगिक गतिविधियों का विकास

लीगा पाट व्यापार में सुगमता
• इंडियन कानून एक्सचेंज गेटवे (एफडीआईआरएच) के अधीन दूसरों को लेनी-देनी सुरक्षित
इन्फ्रास्ट्रूक्चर प्रगति पथ

जब आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है।

— नरेंद्र मोदी
पीएम गतिशक्ति— प्रगति को रप्तार

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी
- नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुगमता
- बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार सुजन
- वस्तु एवं सेवाओं की आवाजाही में लगात और समय की बचत

सड़क, रेल, वायुमाग्म, जलमाग्म, बंदरगाहों का विस्तार

कनेक्टेड भारत का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (किलोमीटर में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ष</th>
<th>किलोमीटर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2014</td>
<td>91,287</td>
</tr>
<tr>
<td>वर्तमान में</td>
<td>1,46,145</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पिछले 10 वर्षों में 54,858 किलोमीटर की वृद्धि

निर्मित सड़क की लंबाई (किलोमीटर में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>साल</th>
<th>किलोमीटर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2013-14</td>
<td>4,260</td>
</tr>
<tr>
<td>2020-21</td>
<td>13,327</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2013-14 से 2020-21 के दौरान 3 गुना वृद्धि

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क (किलोमीटर में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>माह</th>
<th>किलोमीटर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मार्च 2014</td>
<td>3,81,135</td>
</tr>
<tr>
<td>अक्टूबर 2023</td>
<td>7,46,448</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2013-14 से 2020-21 के दौरान निर्माण की गति में 3 गुना वृद्धि
विशेषांक

यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर

• ‘यशोभूमि’ को लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है।
• 11000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ एक भव्य कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं।
• बैठने की अन्य वस्तुएं के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा।
• कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े एलईडी मीडिया अग्रणी से सुसंज्ञित है।
• ‘यशोभूमि’ दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक।

परिवहन परिवेश में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

• वंदे भारत एक्सप्रेस - 2019 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन।
• देश में फिल्मों अलग-अलग रुट पर 68 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित।
• अगले 3 वर्षों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का चिह्नित किया जाएगा। यह ‘मेक इन इंडिया’ का अभूतपूर्व उदाहरण है।
मेट्रो रेल में ‘मेक इन इंडिया’

• 2014: 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन
• 2023: 20 शहरों में 878 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का परिचालन
विमानन क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां

2014
400 विमान
74 हवाई अड्डे

2023
742 विमान
149 हवाई अड्डे
अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में 30 दिसंबर, 2023 को महार्षि वाल्मीकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य नेताओं

आन नागरिकों की हवाई यात्रा का सपना पूरा

1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने की हवाई यात्रा
11 ऑपरेटरों ने 2.43 लाख उड़ानों का संचालन किया

75 हवाई अड्डे
489 मार्ग

*23 सितंबर, 2023 तक*
भारत का टेक्नोलॉजी युग

“हम भारत में आधुनिक डिजिटल अवसंरचना तैयार कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।”
- नरेन्द्र मोदी
चंद्रयान-3 मिशन

• भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना
• लागत प्रभावी अंतरिक्ष अभियानों में भारत ने अपनी क्षमता साबित की
• चंद्रयान-3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों ने बड़ी भूमिका निभाई
• चंद्रयान-3 का मुख्य ध्यान चंद्रमा की सतह की विशेषताओं का एक एकीकृत मूल्यांकन प्रदान करना रहा, जिसमें चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी (रेगोलिथ) के साथ ही चंद्रमा की सतह के तापमान गुण और उसकी सतह के निकट प्लाज्मा वातावरण के तत्व शामिल हैं
• चंद्रयान-3 के लैंडिंग बिंदु को ‘शिव शक्ति बिंदु’ और चंद्रयान-2 के पदविह को ‘तिरंगा बिंदु’ नाम दिया गया
• चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा

आदित्य एल 1 मिशन

• सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन
• इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा
• आदित्य एल। सूर्य की कोरोनल हीटिंग, मास इजेक्शन और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा
गगनयान मिशन

• गगनयान मिशन भारतीय प्रक्षेपण यान पर पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा।
• 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य
• भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

क्या आप जानते हैं?
भारतनेट के तहत 1.98 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार
ई-गवननेंस और सेवाओं की सुगमता

• मई, 2023 तक देश भर में 5.21 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालित; इनमें से कुल 4.13 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं

• रुपे कार्ड के माध्यम से भारत के पहले वैश्विक भुगतान तंत्र में 70 करोड़ भारतीय शामिल

• उमंग ऐप – 905 केंड्र और राज्य सरकारी विभागों की 877 सेवाएं उपलब्ध

• किसान रथ मोबाइल एप्लिकेशन (कृषि उपज के परिवहन के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए 5.84 लाख किसान, किसान संगठन, व्यापारी और सेवा प्रदाता पंजीकृत

• मिशन की प्रगति को ट्रैक और मानचित्र रखने के लिए SBM 2.0 MIS ऐप विकसित किया गया। ऐप SBM Ph II के तहत संपत्ति के डेटा को अपलोड करने की अनुमति देता है। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों को जियो-टैग किया गया है
नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 1.17 करोड़ मानचित्रों को डिजिटल किया गया। 94.23 प्रतिशत गांवों के भूमि अभिलेख कंप्यूटर में दर्ज
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 4.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया।

सेमीकॉन्ड्यूटर इंडिया 2023: भारत बन रहा सेमीकंडक्टर का उभरता हब

- भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक वित्तीय प्रोत्साहन
- सेमीकंडक्टर फैल्स, डिस्प्ले फैल्स और अन्य केंद्रों को स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% तक समान वित्तीय सहयोग
- यह दस साल की अवधि में भारत की जीडीपी में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये जोड़ेगा।
नॉर्थ-ईस्ट विकास का नया इंजन

“आज नॉर्थ-ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं।”

— नरेन्द्र मोदी
शांति और समृद्धि के लिए समझौते

- एनएलएफटी (एसडी) त्रिपुरा शांति समझौता (2019)
- बूढ़ पुनवांस समझौता (2020)
- बोडो शांति समझौता (2020)
- कार्बी आंगलोंग शांति समझौता (2021)
- एनएससीएन (आईएम) के साथ बुनियादी समझौता (2015)
- आदिवासी असम शांति समझौता (2022)
पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

• पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) का बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर में ऐलान; 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन

• ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और हथससंसगमारी, नेमाड़ा, कमलाबाड़ी एवं गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच रो-रो सेवा की शुरुआत

• असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीसबल के पास बोगीबि के रेल-सह सड़क पुल उत्तर और दक्षिण किनारों पर लिंक ताइनों (लंबाई-73 किमी) के साथ डिसेंबर 2018 में पूरा हुआ- 5,920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत

• 2014 से पहले उत्तर-पूर्व में केवल 9 हवाई अड्डे थे, पिछले नौ साल में उत्तर-पूर्व में 7 नए एयरपोर्ट बने

• मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के रानी गाइडिंल्लू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची

• मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मिलीं

• पूर्वोत्तर में 146.559 किमी की लंबाई की 121 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, बहरी 18.628 किमी की 25 सुरंगें परिचालन में हैं

• पूर्वोत्तर को आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है, स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत अन्य विभिन्न रूपों एवं सुविधाओं का निर्माण

• पूर्वोत्तर की कई जगहों जैसे तुइरर्ल, पारे और कामेंग में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

• लोक रुझान सिरी पनबिजली परियोजना का निर्माण
प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में 'सेंगोल' स्थापित किया
भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

स्ट्रैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली

जेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ, नई दिल्ली
• स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता से जुड़ी भूमिका प्रदर्शित करने के लिए कोलकाता में स्थापित बिपलोबी भारत गैलरी का उदघाटन

• सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ का नई दील्ली में निर्माण

• गुर्मनाम नायकों को उद्धत तरीके से सम्मानित करने के प्रयास में देश ने 2022 को लघुत्तम बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मनाया। लघुत्तम बोरफुकन (24 नवंबर, 1622 - 25 अप्रैल, 1672) असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे, जिन्होंने मुगलों को हराया और औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोका।
भारत मंडपम

‘भारत मंडपम’ आद्यन है भारत के साम्यत्थ का, भारत की नई ऊर्जा का।
‘भारत मंडपम’ दर्शन है, भारत की भव्यता का और भारत की इच्छाशक्ति का।

— नरेन्द्र मोदी

• भारत मंडपम की उत्पत्ति भगवान बसवे्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है, जो सार्वजनिक समारोहों के लिए एक मंडप था।
• सम्मेलन केंद्र भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है।
• भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 18 टन है। यह अष्टधातु से बनी सबसे ऊंची मूर्ति है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए।

प्राचीन काल की धरोहरों को वापस लाया गया।

• 2014 से अब तक प्राचीन काल की 238 अनमोल मूर्तियों को सफलतापूर्वक लाया गया।
सांस्कृतिक स्थलों का विकास

महाकाल लोक कॉर्टिडोर
काशी विष्णुनाथ कॉर्टिडोर
अयोध्या धाम
केदारनाथ धाम
सोमनाथ
प्रयावरण और सतत विकास

“भारत प्रकृति के साथ सद्वार में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

— नरेन्द्र मोदी
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

• वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल
• इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है
• यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा

अक्षय ऊर्जा में भारी वृद्धि

• अक्षय ऊर्जा (आरई) की स्थापित क्षमता में पिछले नौ वर्षों में 2.37 गुना की वृद्धि
• भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है
• सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से सितंबर, 2023 के बीच 2.63 गीगावॉट से बढ़कर 71.78 गीगावॉट से अधिक हुई, सौर पार्क योजना 20 गीगावॉट से दोगुना बढ़कर 40 गीगावॉट हुई। दरों में 1.99 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड निचला स्तर प्राप्त।
• 2030 तक 5 अरब टन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के प्रति वर्ष उत्पादन में सहायता के लिए 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।

![Diagram showing solar energy capacity increase](image)
गोबर-धन योजना

• गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गनिक वायु-एग्लो रिसोसेंज धन) योजना को औपचारिक रूप से 30 अप्रैल, 2018 को एसबीएम (जी) के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया।

• गोबर-धन भारत सरकार की सकुलर इकोनॉमी और ‘समिन लाइफ’ अभियान के अनुरूप ‘वेस्ट टू वेलथ’ पहल है।

• ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि गोबर और ठोस कृषि कवरा को खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके जैव-अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और धन और ऊर्जा पैदा करने के लिए सामुदायिक परियोजनाओं की स्थापना की जाए।

• एसबीएम (जी) के दूसरे चरण में सामुदायिक गोबर-धन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये तक का प्रावधान है। एसबीएम (जी) के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति जिला कम से कम 1 गोबर-धन संयंत्र अनिवार्य है।

796
जैव-गैस/सीबीजी प्लांट - पूर्ण/क्रियाशील

424
जैव-गैस/सीबीजी प्लांट - निर्माणाधीन

443
जिले जैव-गैस के तहत + 132 जिले सीबीजी के तहत
उजाला योजना

- सभी को सस्ती दरों पर एलईडी (उजाला) के उद्देश्य से 2015 में लॉन्च
- दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सब्सिडी वाला स्वदेशी प्रकाश व्यवस्था का कार्यक्रम
- भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एलईडी बाजार है
अंतर्राष्ट्रीय ऊजाला एजेंसी (आईईए) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उजाला से उपभोक्ता के विजली बिल में प्रति वर्ष 16 अरब रुपये से अधिक की बचत हुई है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभयान (पीएम-कुसुम) योजना

• अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने के लिए फरवरी, 2019 में प्रारंभ
• सौर ऊर्जा चलने के माध्यम से 35 लाख से ज्यादा किसानों को ऊर्जा

10,000 मेगावाट के सौर/अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित
20 लाख सौर कृषि पंप लगाए गए
ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंप सौर ऊर्जा चलने का प्रयास जारी

एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड

• अक्टूबर, 2023 तक स्थापित सौर क्षमता 71.78 मीगावाट हुई
• एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को साकार करने के लिए वैश्विक ग्रिड बनाने का प्रयास जारी
प्रधानमंत्री ने दुनिया से ‘पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली’ यानी LiFE को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका विज्ञन न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि ऊर्जा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी जोर देता है। इन समाधानों में ऊर्जा कुशल एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैं।
नमािि गंगे

• गंगा नदी का कायाकल्य करने, प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने और संरक्षण के लिए 2014 में प्रारंभ

• अब तक 37,985 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 448 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है; 260 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और उन्हें चालू कर दिया गया है

पीएम-ई-बस सेवा

• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी

• इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी

• इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है

16-31 मार्च, 2024
प्रधानमंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ‘स्वच्छता के लिए श्रमदान’ किया। देशभर में 8.75 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के आदान पर ‘एक तारीख, एक घंटा, एक साथ’ कार्यक्रम में भाग लिया।
@ Joseph R. Biden Jr.
President of the United States

One Earth. One Family. One Future.
That's the focus of this G20 Summit: building resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future that represents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone.

@ Rishi Sunak
Prime Minister of the United Kingdom

Stronger together. Stronger united.
Thank you Narendra Modi for a historic G20 and the Indian people for such a warm welcome.
From global food security to international partnerships, it's been a busy but successful summit.
Giorgia Meloni
Prime Minister of Italy

I thank the Prime Minister of India Narendra Modi for his stewardship of this Presidency #G20, which has put forward an ambitious agenda on global challenges. We have worked together to ensure the success of this Summit and we will continue to coordinate in bilateral relations and also in view of the Italian Presidency of the G7.

#G20India

Emmanuel Macron
President of France

वसुधाव कुटुम्बकम्
The world is one family.
Le monde est une seule famille.

Anthony Albanese
Prime Minister of Australia

A successful G20 meeting hosted by Narendra Modi in New Delhi today followed by a good bilateral discussion about concluding the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between Australia and India.
X@ Ursula von der Leyen
President of the European Commission

Thank you for your skillful leadership of the G20, @narendramodi.

A strong partnership with India is paramount for Europe. Glad to see our Trade & Tech Council in action. And to have launched with you an historic project, the India – Middle East – Europe Economic Corridor.

X@ Bill Gates
Co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation

The G20 reached a groundbreaking consensus on the role of digital public infrastructure as a critical accelerator of the Sustainable Development Goals. I’m optimistic about the potential of DPI to support a safer, healthier, and more just world. Kudos to PM Narendra Modi.

X@ Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director-General, World Health Organization

We welcome the G20 Leaders’ comprehensive commitment to health in the New Delhi Declaration, including to strengthen WHO. We will continue to work closely with G20 countries towards a healthier, safer, fairer future for all.
नई दिल्ली में 26 फरवरी, 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी के राष्ट्रीय परिषद ‘संकल्प पत्र सुझाव अभियान’ एवं ‘विकसित भारत – मोदी की गारंटी रथ’ का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा।

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें
आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विवाह के संचरण में अपना योगदान!

सदस्यता प्रमाण

नाम : .................................................................
पूरा पता : .................................................................
.................................................................
.................................................................
दूरभाष :................................. मोबाइल : (1)................................. (2).................................
ईमेल : .................................................................

<table>
<thead>
<tr>
<th>सदस्यता</th>
<th>एक वर्ष</th>
<th>तीन वर्ष</th>
<th>आजीवन सदस्यता (हिंदी/अंग्रेजी)</th>
<th>आजीवन सदस्यता (हिंदी+अंग्रेजी)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>₹350/-</td>
<td>₹1000/-</td>
<td>₹3000/-</td>
<td>₹5000/-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(भुगतान विवरण)
चेक/द्राफ्ट क्र. : ................................................................. दिनांक : .................................................................
बैंक : .................................................................
नोट : ढांढी / चेक ‘कमल संदेश’ के नाम दें।
मगर आईटी और नकद पूरे विवाह के साथ स्वीकार किए जाएगे।

(हस्ताक्षर)

अपना ढांढी/बैंक निव्वल पते पर में ज्ञापन दें
ड्र. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुबर्मयम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in
कमल संदेश: राष्ट्रीय विवाह की प्रतिनिधित्व पात्रका
नई दिल्ली में 21 सितंबर, 2023 को नए संसद भवन में ‘संगीत’ स्थापित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं साक्षात अध्यक्ष श्री ओम प्रियाता

नई दिल्ली में 05 फरवरी, 2024 को संसद भवन में धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 11 जनवरी, 2024 को अपने आवास पर मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
“22 जनवरी, 2024—यह कैंपेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, एक नए कालचक्र का उद्गम है।” — नरेंद्र मोदी